भारत सरकार

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1741

जिसका उत्तर 30 जुलाई, 2025 को दिया जाना है ।

8 श्रावण, 1947 (शक)

बिहार में डिजिटल प्रशिक्षण केंद्र

1741. श्री अभय कुमार सिन्हा:

क्या इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत बिहार की ग्राम पंचायतों में सामान्य सेवा केंद्र (सीएससी) और डिजिटल प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए हैं;

(ख) यदि हाँ, तो इन केंद्रों की संख्या का ब्यौरा क्या है तथा राज्य-वार और जिला-वार उनकी कार्यात्मक स्थिति और संचालन का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन केंद्रों के माध्यम से ग्रामीण नागरिकों को डिजिटल साक्षरता, सरकारी सेवाओं तक पहुँच और ई-गवर्नेंस संबंधी सुविधाएँ प्रदान की जा रही हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार ने इन केंद्रों के प्रभाव की निगरानी के लिए कोई मूल्यांकन तंत्र स्थापित किया है और यदि हाँ, तो इसकी मुख्य विशेषताओं का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद)

(क) से **(घ):** भारत सरकार ने नागरिक-केंद्रित सेवाएँ, अर्थात् सरकार से नागरिक (जी2सी) सेवाएँ और व्यवसाय से नागरिक (बी2सी) सेवाएँ प्रदान करने हेतु परियोजना सीएससी 2.0 के अंतर्गत सामान्य सेवा केंद्र (सीएससी) स्थापित करने हेतु एक परियोजना शुरू की है। परियोजना सीएससी 2.0 का कार्यान्वयन सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के माध्यम से किया जा रहा है।

सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड ने बताया है कि जून 2025 तक, देश में ग्राम पंचायत स्तर पर कुल 10.12 लाख (लगभग) सीएससी पंजीकृत हैं और 4.36 लाख (लगभग) सीएससी कार्यरत हैं। बिहार राज्य में, ग्राम पंचायत स्तर पर 98 हज़ार (लगभग) सीएससी पंजीकृत हैं और 46 हज़ार (लगभग) कार्यरत हैं। पंजीकृत और कार्यरत सीएससी का जिलावार विवरण अनुबंध-I में दिया गया है।

ये सीएससी ग्रामीण भारत में डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान (पीएमजीदिशा) में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। पीएमजीदिशा योजना का उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को बुनियादी डिजिटल साक्षरता प्रदान करना है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि प्रत्येक परिवार का एक व्यक्ति आवश्यक डिजिटल कौशल प्राप्त करे।पीएमजीदिशा योजना के अंतर्गत कुल 6.39 करोड़ लाभार्थियों को प्रमाणित किया गया, जिनमें से 74 लाख से अधिक लाभार्थी बिहार से हैं। पीएमजीदिशा योजना के अंतर्गत बिहार में कुल 16,173 सामान्य सेवा केंद्र (सीएससी) प्रशिक्षण केंद्रों के रूप में पंजीकृत हैं।

इन सीएससी के माध्यम से 800 से अधिक सेवाएं प्रदान की जा रही हैं, जिनमें सरकारी सेवाएं, वित्तीय सेवाएं और आधार से संबंधित सेवाएं, सामाजिक कल्याण सेवाएं, शिक्षा, टेलीमेडिसिन, उपयोगिता भुगतान, बैंकिंग और बीमा सेवाएं आदि शामिल हैं।

सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड ने सीएससी के प्रदर्शन और प्रभाव का आकलन करने के लिए एक मूल्यांकन तंत्र स्थापित किया है। इस मूल्यांकन प्रणाली में प्रत्येक केंद्र पर लेनदेन, सेवाओं की उपलब्धता और गतिविधियों की निगरानी के लिए रीयल-टाइम डैशबोर्ड शामिल हैं। ग्राम स्तरीय उद्यमियों (वीएलई) का मासिक बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण, निरंतर कार्यक्षमता सुनिश्चित करने के लिए सीएससी की स्थिति का सत्यापन, जिला-स्तरीय क्षेत्रीय टीमों द्वारा जियो-टैग्ड मोबाइल एप्लिकेशन का उपयोग करके सीएससी का भौतिक सत्यापन, और सीएससी की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने के लिए समय-समय पर प्रभाव आकलन भी किए जाते हैं।

******

अनुबंध-I

बिहार में सीएससी का जिलावार विवरण

स्रोत: सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड

जिले का नाम	ग्राम पंचायत स्तर पर पंजीकृत सीएससी	ग्राम पंचायत स्तर पर कार्यात्मक सीएससी
अररिया	3,570	1,454
अरवल	486	227
औरंगाबाद	1,857	866
बांका	2,401	1,262
बेगूसराय	2,473	1,205
भागलपुर	3,172	1,563
भोजपुर	1,763	866
बक्सर	1,263	671
दरभंगा	4,560	2,165
पूर्वी चंपारण	4,950	2,267
गया	3,205	1,617
गोपालगंज	2,839	1,393
जमुई	1,931	1,001
जहानाबाद	621	321
कैमूर(भभुआ)	1,318	686
कटिहार	3,931	1,718
खगड़िया	1,576	900
किशनगंज	1,757	815
लखीसराय	744	385
मधेपुरा	2,678	970
मधुबनी	4,786	2,324
मुंगेर	936	531
मुजफ्फरपुर	5,375	2,340
नालंदा	1,918	957
नवादा	1,642	797
पटना	3,079	1,539
पूर्णिया	3,660	1,566
रोहतास	2,063	952
सहरसा	2,261	922
समस्तीपुर	4,616	2,083
सारन	3,796	1,753
शेखपुरा	453	207
शिवहर	678	303
सीतामढ़ी	3,575	1,593
सिवान	3,335	1,447
सुपौल	2,793	1,304
वैशाली	3,063	1,555
पश्चिम चंपारण	3,570	1,551
कुल	**98,694**	**46,076**

******